भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 274

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कार्यान्वयन

274. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अप्रैल, 2023 में नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के शुरू होने के बाद से इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी प्रगति क्या है और कितने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं;

(ख) क्या नई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के संबंध में राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पहल के अंतर्गत नामांकित उद्यमियों अथवा स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या कितनी है और ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (वीएलएसटीएल) की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित मृदा मानचित्रण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम कार्यान्वित की गई है। अब तक देश भर में 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) तैयार किए जा चुके हैं तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1706.18 करोड़ रूपये की राशि जारी की जा चुकी है। अब तक देश भर में 8272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ (1068 स्थैतिक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, 163 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, 6376 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ तथा 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ) स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण नामक अधीनस्थ कार्यालय भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के माध्यम से मृदा डेटाबेस के अनुप्रयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट (आईडब्ल्यूएमपी), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और मृदा सर्वेक्षण एवं मानचित्रण जैसे

विषयों पर अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (03 दिवसीय) आयोजित करता है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वर्ष 2024 में, पश्चिम बंगाल सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि, वन और मृदा एवं जल संरक्षण विभागों के अधिकारियों के लिए और वर्ष 2025 में जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(ग): अब तक, 17 राज्यों में 665 ग्राम-स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ (वीएसटीएल) स्थापित की जा चुकी हैं। इनमें उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा स्थापित प्रयोगशालाएँ शामिल हैं, लेकिन उनका डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ): अब तक, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण ने 40 आकांक्षी जिलों को शामिल करते हुए लगभग 290 लाख हेक्टेयर के लिए 1:10,000 स्केल पर मृदा मानचित्रण पूरा कर लिया है। किसानों द्वारा उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण ने 21 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1,987 ग्राम-स्तरीय मृदा उर्वरता मानचित्र भी तैयार किए हैं।

*****